भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2841
18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान

2841. **डॉ. शशि थरूर**:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में राज्य मत्स्य विभाग के साथ केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के सहयोग से तटीय जलीय कृषि और संबंधित समुद्री परियोजनाओं को बढ़ावा देकर तटीय समुदायों के लिए सतत और वैकल्पिक आय के अवसर पैदा होंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त पहलों से कितने तटीय समुदायों और मछुआरों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है;
(ग) इन समुदायों में आय या रोजगार के अवसरों में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) योजना में कौशल विकास कार्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए संभावना और स्तर तथा कार्यावधि का ब्यौरा क्या है;
(ङ) समुद्री जलीय कृषि में स्थानीय क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए डिजाइनों का ब्यौरा और संख्या क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (ङ): केरल सरकार ने सूचित किया है कि सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआई) और केरल के राज्य मत्स्यपालन विभाग के बीच सहयोग से तटीय जलकृषि और अन्य समुद्री संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं को संवर्धित कर तटीय समुदायों के लिए सतत (सस्टेनेबल) और वैकल्पिक आय के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह सहयोग राज्य को केरल के तट पर समुद्री कृषि गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बना सकता है, विशेष रूप से तकनीकी सलाह प्राप्त करके ओपन सी केज फ़ार्मिंग करने की व्यवहार्यता के अध्ययन और कोबिया और पोम्पानो जैसी कल्टिवेबल हाइ-वैल्यू मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्ता वाले सीड प्राप्ति, जिससे मछुआरा समूहों के लिए वैकल्पिक आय स्रोत के रास्ते खुलेंगे।

राज्य द्वारा सीएमएफआरआई की सहायता समुद्री स्थानिक योजना तैयार करने और मछुआरों के लिए आय स्रोतों में विविधता लाने के लिए सीप और समुद्री शैवाल (सी वीड) की खेती करने की संभावनाओं की खोज करने के अलावा मत्स्य किसानों को निरंतर वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने में भी ली जाती है। पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत कोस्टल फिशिंग विलेज में आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की स्थापना के लिए सीएमएफआरआई की तकनीकी विशेषज्ञता का भी लाभ उठाया जा रहा है, जो पारंपरिक मछुआरों के लिए आवास जीर्णोद्धार और सतत आजीविका सुनिश्चित करता है। सी रेंचिंग कार्यक्रमों और ऑपन सी केज फ़ार्मिंग के लिए पोम्पानो और कोबिया के गुणवत्ता वाले सीड के प्रावधान के लिए भी सीएमएफआरआई की सेवा ली जाती है। राज्य द्वारा राज्य में सी फिनफिश हैचरी स्थापित करने के लिए सीएमएफआरआई की सीड उत्पादन की तकनीकी विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जाता है।

केरल में समुद्री मत्स्य उत्पादन के सांख्यिकीय डेटा विश्लेषण में सीएमएफआरआई के सहयोग की भी विभाग द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है और साथ ही समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों की सततता सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण और प्रबंधन उपायों के अन्य पहलुओं के अलावा वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के न्यूनतम लीगल साइज़ जैसे नियमों को जारी रखने के लिए तकनीकी सलाह भी दी गई है। सीएमएफआरआई मछुआरों और उद्यमियों के लिए आधुनिक जलकृषि तकनीकी में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है, जो ओर्नमेंटल फिशरीज़ की ब्रीडिंग और ट्रेड को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, आईसीएआर-सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोच्चि ने बताया कि आईसीएआर-सीएमएफआरआई किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लाभ के लिए विभिन्न समुद्री कृषि प्रौद्योगिकियों पर नियमित रूप से अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण आयोजित करता है।

इसके अलावा, विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान प्रमुख योजना 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 574.90 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ केरल सरकार के 1358.10 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस अवधि के दौरान केरल को 344.15 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि भी जारी की गई है।

*****